



भारत का वारपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 205]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 18, 2010/श्रावण 27, 1932

No. 205]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 18, 2010/SHRAVANA 27, 1932

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 13 अगस्त, 2010

सं. टीएएमपी/37/2008-सीएचपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 और 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, महापत्तन न्यास प्राधिकरण एतद्वारा, ग्रेनाइट्स प्रखंडों पर चेनै पत्तन न्यास द्वारा उगाहे जा रहे क्रेनेज प्रभार के संबंध में हिन्दुस्तान चैम्बर ऑफ कार्मस से प्राप्त मामले (संदर्भ) को, एतद्वारा, संलग्न आदेश के अनुसार निपटाता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएएमपी/37/2008-सीएचपीटी

हिन्दुस्तान चैम्बर ऑफ कार्मस

....

आवेदक

आदेश

(आज जुलाई, 2010 के 23वें दिन पारित)

हिन्दुस्तान चैम्बर ऑफ कार्मस ने ग्रेनाइट प्रखंडों पर चेनै पत्तन न्यास (सीएचपीटी) द्वारा क्रेनेज प्रभारों की उगाही के संबंध में दिनांक 11 दिसम्बर, 2007 के अपने पत्र द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था।

2. अभ्यावेदन दिनांक 18 दिसंबर 2007 के हमारे पत्र के माध्यम से सीएचपीटी को उनकी टिप्पणी के लिए अग्रेषित किया गया था। सीएचपीटी से यह भी अनुरोध किया गया था कि वह पोत भी परिवहन मंत्रालय द्वारा 1991 में कथित रूप से जारी किए गए उस आदेश की एक प्रति भी प्रस्तुत कर, एचसीसी ने जिसका संदर्भ दिया था।

3. सीएचपीटी ने दिनांक 29 मई 2008 के अपने पत्र के माध्यम से दिनांक 5 अक्टूबर 1994 की अधिसूचना के माध्यम से, जिसमें निर्यात के लिए ग्रेफाइट प्रखंडों की हैवीलिफ्ट प्रभारों से छूट प्रदान की गई थी, पत्तन द्वारा जारी किए गए दरमान के संशोधन की एक प्रति के साथ अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं। बाद में,

हि.चै.कामर्स ने दिनांक 31 मई 2008 के अपने पत्र के माध्यम से, सीएचपीटी द्वारा 29 मई 2008 के अपने पत्र में उठाए गए बिन्दुओं पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं। हि.चै.कामर्स का अभ्यावेदन, दिनांक 29 मई 2008 के अपने पत्र के माध्यम से मिली सीएचपीटी की टिप्पणियां और दिनांक 31 मई 2008 के पत्र के माध्यम से उस पर हि.चै.कामर्स की टिप्पणियां संक्षेप में नीचे सारणी बद्ध दी गई हैं:-

क्र.सं.	11 अक्टूबर 2007 के पत्र में हि.चै.कामर्स द्वारा उठाए गए बिंदु	हि.चै.कामर्स के अभ्यावेदन पर सीएचपीटी की टिप्पणियां दिनांक 29 मई 2008	सीएचपीटी की टिप्पणियां पर हि.चै.कामर्स की टिप्पणियां दिनांक 31 मई 2008
1.	<p>सीएचपीटी के दरमान के मान 11-II नोट (4) कहता है कि हैवी लिफ्ट प्रभार निर्यात के लिए ग्रेनाइट पत्थरों पर लागू नहीं है। 1991 में, पोत परिवहन मंत्रालय ने अनगढ़ ग्रेनाइट प्रखंडों को हैवी लिफ्ट और क्रेनेज प्रभारों से छूट देते हुए आदेश जारी किए थे। सीएचपीटी अपने दरमान में नियमों की इस प्रकार व्याख्या कर रहा है जिस ने, निजी क्रेन किराए पर लेने के साथ-साथ 150 टन फ्लोटिंग क्रेन के लिए लागू 10% की गणना करते हुए उपयोगकर्ता से बड़ी राशि का भुगतान करवा कर ग्रेनाइट प्रखंडों के निर्यात को अधिक खर्चीला बना दिया है।</p> <p>हि.चै.कामर्स ने नियमों की ठीक-ठीक व्याख्या करने का अनुरोध किया है और उसकी राय में क्रेन किराया प्रभार पर 10% जैसा मान 10 में दिखाया गया है, ही</p>	<p>हि.चै.कामर्स के अभ्यावेदन पर सीएचपीटी की टिप्पणियां दिनांक 29 मई 2008</p> <p>5 अक्टूबर 1994 को अधिसूचना सं.टी 2 /23 /3218 /93 /एआर के माध्यम से दरमान में इस आशय का संशोधन जारी किया गया था कि निर्यात के लिए ग्रेनाइट प्रखंडों पर हैवी लिफ्ट प्रभार से छूट प्रदान की है। इस प्रकार, हैवी लिफ्ट प्रभारों की दर के आधार पर 10% की गणना असमर्थनीय है और शुरू से ही अस्वीकार्य है। पत्तन ने इस बात की पुष्टि की है कि निजी क्रेनों को अनुमति प्रदान करने के संबंध में दरमान में किया गया संशोधन (प्रचालन में) दक्षता लाने और निजी क्रेनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए था। इस प्रकार मान-11 का नोट (6) राजस्व बढ़ाने के लिए नहीं, प्रक्रिया को अधिक सरल बनाने के लिए शामिल किया गया था।</p> <p>पत्तन ने इस की पुष्टि की है कि चूंकि ग्रेनाइट प्रखंड सीधे-सीधे ट्रेलर से पोत पर लादे जाते हैं कोई क्रेनेज प्रभार नहीं उगाहा जाता है। यह इस बात को न्यायोचित ठहराता है कि जब इस कार्गो द्वारा सामान्य रूप से किसी क्रेनेज का भुगतान नहीं किया जाता है तो क्रेन प्रभार पर 10% की उगाही अनुचित है। 10% प्रभार की उगाही ग्रेनाइट प्रखंडों के निर्यात को अधिक खर्चीला बनाती है।</p> <p>सीएचपीटी के दरमान के मान-11 के नोट (6) को निम्नानुसार संशोधित किया जाए:</p> <p>“पत्तन प्रचालन के लिए अनगढ़ ग्रेनाइट पत्थरों के निर्यात को छोड़कर पक्ष के अनुरोध पर दरमान में विनिर्दिष्ट प्रभारों के भुगतान पर निजी क्रेनों को अनुमति प्रदान की जाएगी।”</p>	<p>सरकार ने अपनी अधिसूचना सं.टी 2 /23 /3218 /93 /एआर (शुद्ध पर्ची सं. 7) दिनांक 5 अक्टूबर 1994 के माध्यम से अनगढ़ ग्रेनाइट प्रखंडों पर हैवी लिफ्ट प्रभार से छूट प्रदान की है। इस प्रकार, हैवी लिफ्ट प्रभारों की दर के आधार पर 10% की गणना असमर्थनीय है और शुरू से ही अस्वीकार्य है। पत्तन ने इस बात की पुष्टि की है कि निजी क्रेनों को अनुमति प्रदान करने के संबंध में दरमान में किया गया संशोधन (प्रचालन में) दक्षता लाने और निजी क्रेनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए था। इस प्रकार मान-11 का नोट (6) राजस्व बढ़ाने के लिए नहीं, प्रक्रिया को अधिक सरल बनाने के लिए शामिल किया गया था।</p> <p>पत्तन ने इस की पुष्टि की है कि चूंकि ग्रेनाइट प्रखंड सीधे-सीधे ट्रेलर से पोत पर लादे जाते हैं कोई क्रेनेज प्रभार नहीं उगाहा जाता है। यह इस बात को न्यायोचित ठहराता है कि जब इस कार्गो द्वारा सामान्य रूप से किसी क्रेनेज का भुगतान नहीं किया जाता है तो क्रेन प्रभार पर 10% की उगाही अनुचित है। 10% प्रभार की उगाही ग्रेनाइट प्रखंडों के निर्यात को अधिक खर्चीला बनाती है।</p> <p>सीएचपीटी के दरमान के मान-11 के नोट (6) को निम्नानुसार संशोधित किया जाए:</p> <p>“पत्तन प्रचालन के लिए अनगढ़ ग्रेनाइट पत्थरों के निर्यात को छोड़कर पक्ष के अनुरोध पर दरमान में विनिर्दिष्ट प्रभारों के भुगतान पर निजी क्रेनों को अनुमति प्रदान की जाएगी।”</p>

	उगाहा (वसूल किया जाना चाहिए ।	<p>सीएचपीटी के दरमान के मान-11 का नोट (6) कहता है,</p> <p>“पत्तन प्रचालन के लिए पक्ष के अनुरोध पर दरमान में विनिर्दिष्ट प्रभारों के भुगतान पर निजी क्रेनों को अनुमति प्रदान की जाएगी।”</p> <p>निजी क्रेनों की तैनाती के लिए 10% प्रभारों के भुगतान से ग्रेनाइट प्रखंडों को छूट के लिए धारा 6 में कोई प्रावधान नहीं है।</p> <p>चूंकि ग्रेनाइट प्रखंड सीधे-सीधे लॉरी / ट्रेलर से पोत लदान किए जाते हैं कोई क्रेनेज प्रभार नहीं उगाहा गया है।</p> <p>यह केवल अन्तिम दो वर्षों के लिए है कि ग्रेनाइट प्रखंडों के प्रहस्तन में सक्षम हैकी लिपट हार्बर मोबाइल क्रेन उपलब्ध हैं। यदि ग्रेनाइट प्रखंडों का प्रहस्तन करने वाली प्राइवेट क्रेनों को 10% प्रभार के भुगतान से छूट प्रदान करने का इरादा होता तो उसका सीएचपीटी के दरमान के मान-11 के नोट (4) अथवा नोट (6) में स्पष्ट उल्लेख होता। इस प्रकार के प्रावधान के अभाव में पत्तन के लिए यह उचित नहीं होगा कि वह उपयोग कर्त्ताओं के अनुरोध के आगे झुके और ग्रेनाइट प्रखंडों का प्रहस्तन करने वाली निजी क्रेनों को छूट प्रदान करे।</p> <p>प्राधिकरण समुचित निर्णय ले और उसे सीएचपीटी को बता दे।</p>
--	-------------------------------	--

4. प्रशुल्क मार्गदर्शी 2005 की धारा 3.1.5 के अनुसार यह प्राधिकरण व्यक्तिगत उपयोगकर्त्ताओं द्वारा दाखिल किए गए अप्यावेदनों को विचारार्थ स्वीकार कर सकता है यदि उनमें प्रशुल्क / दरमान का निर्धारण सम्मिलित है। इस तथ्य के मद्दे-नजर कि हि.चै.कामर्स ने दरमान में प्रदत्त संशर्तताओं के अनुप्रयोग के विषय में मुद्दा उठाया है और प्राधिकरण ही इस दिशा में निर्णय लें, अपनाई गई सामान्य परामर्शी प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए निर्णय लिया गया था कि हि.चै.कामर्स से प्राप्त संदर्भ पर कार्रवाई की जाए।

5. तदनुसार, दिनांक 11 दिसंबर 2007 के अपने पत्र के माध्यम से हि.चै.कामर्स से प्राप्त संदर्भ, हि.चै.कामर्स के संदर्भ पर सीएचपीटी का प्रत्युत्तर दिनांक 29 मई 2008 और सीएचपीटी द्वारा उठाए गए बिन्दुओं पर टिप्पणियां करते हुए हि.चै.कामर्स का पत्र दिनांक 31 मई 2008 की एक-एक प्रति सम्बद्ध उपयोगकर्त्ता संगठनों और सीएचपीटी द्वारा सुझाए गए अतिरिक्त उपयोगकर्त्ताओं को दिनांक 5 सितंबर 2008 के पत्र के माध्यम से भेजी गई थीं। विभिन्न उपयोगकर्त्ताओं / उपयोगकर्त्ता संगठनों से प्राप्त टिप्पणियां सीएचपीटी को उसकी टिप्पणियों के लिए भेजी गई थीं। सीएचपीटी ने प्रतिपूरक सूचना पर अपनी टिप्पणी पेश की।

6. इस प्रकरण में 29 जून 2010 को सीएचपीटी के परिसर में एक संयुक्त सुनवाई आयोजित की गई थी। हि.चै.कामर्स तथा सीएचपीटी ने इस बैठक में अपने-अपने पक्ष रखे।

7. इस प्रकरण में परामर्श से संबंधित प्रक्रिया इस प्राधिकरण के कार्यालय में रिकार्ड्स पर उपलब्ध है। प्राप्त टिप्पणियों के सारांश की एक प्रति-संबद्ध पक्षों को अलग से भेजी लाएगी। ये विवरण हमारे वैब साइट <http://tariffauthority.gov.in> पर उपलब्ध करवाई जाएगी।

8. प्रकरण पर प्रक्रिया करते समय संग्रहित सूचना की समग्रता के संदर्भ से निम्नलिखित स्थिति उभरती हैः—

- (i) सीएचपीटी के, अक्तूबर 2002 में निर्धारित दरमान को संशोधित करते हुए इस प्राधिकरण ने 7 मार्च को एक आदेश पारित किया गया था। मार्च 2006 में अनुमोदित दरमान में पत्तन की 50 टन क्रेन और 150 टन फ्लोटिंग क्रेन के उपयोग के लिए प्रावधान सन्निहित हैं। जब 30 टन से अधिक वजन के कार्गो का कोई पैकेज पोत की क्रेन द्वारा उतारा जाता है अथवा पोत पर लादा जाता है तो प्रदत्त प्रभारों का केवल 50% ही पत्तन द्वारा उपयोगकर्ता से वसूल किया जाएगा। किन्तु, ग्रेनाइट प्रखंडों के निर्यात को प्रदत्त क्रेनेज प्रभार के 50% प्रभार से छूट प्राप्त है।
- (ii) यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि भारत सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर सीएचपीटी ने दिनांक 5 अक्तूबर 1994 की एक अधिसूचना द्वारा अपने दरमान में संशोधन किया था जिसके अनुसार जब कभी पोत की क्रेनों का उपयोग करते हुए ग्रेनाइट पत्थरों का निर्यात किया जाएगा, उन्हें हैवीलिफ्ट प्रभारों से छूट प्राप्त होगी।
- (iii) अक्तूबर 2002 में इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दरमान में एक प्रावधान था जिसके अनुसार, यदि पत्तन न्यास के पास ये उपकरण नहीं हो तो सीएचपीटी के तत्कालीन प्रवलित दरमान में विनिर्दिष्ट प्रभारों के 10% की वसूली पर फत्तन प्रचालनों के लिए निजी क्रेनों को अनुमत करने हेतु सीएचपीटी को अधिकार प्रदान किया गया था। जैसाकि सीएचपीटी द्वारा उपयोगकर्ताओं के अनुरोध पर प्रस्तावित किया गया था मार्च 2006 के प्रशुल्क आदेश में, अक्तूबर 2002 के प्रशुल्क आदेश में प्रदत्त प्रावधान को निजी उपकरणों पर प्रदत्त प्रभार तब भी लगाने के लिए जब ऐसे उपकरण सीएचपीटी के पास उपलब्ध हो, थोड़ा-सा परिवर्तन किया गया था। संयोगवश, मार्च 2006 का प्रशुल्क आदेश भी, सभी संबद्ध उपयोगकर्ता संगठनों के साथ उनकी चर्चा के बाद सीएचपीटी द्वारा दाखिल एक मत प्रस्ताव के आधार पर पारित किया गया था।
- (iv) निजी क्रेनों द्वारा प्रहसित कार्गो के लिए प्रदत्त क्रेनेज प्रभारों का 10% लगाया जाना प्रदत्त सामान्य क्रेनेज प्रभार आकर्षित करने वाले ऐसे कार्गो के लिए संयोगवश ही है। चूंकि ग्रेनाइट प्रखंडों का निर्यात प्रेषण को सामान्य हैवीलिफ्ट प्रभारों से छूट प्राप्त है तो ऐसे ग्रेनाइट प्रखंड निजी क्रेनों द्वारा प्रहसित किए जाते हैं तो ऐसे ग्रेनाइट प्रखंडों को 10% प्रभारों के लगाए जाने से छूट प्रदान करने वाले तदनुरूप प्रावधान का अभाव मार्च 2006 में अनुमोदित दरमान में एक चूक जान पड़ता है। उपयुक्त / प्रासंगिक समय पर इस प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत दरमान, उपयोगकर्ता संगठनों के साथ सीएचपीटी के परामर्श का परिणाम था। तथापि, 10% प्रभार लगाने से ग्रेनाइट प्रखंडों को छूट प्रदान करने वाले प्रासंगिक प्रावधान के दरमान में न होने पर, किसी ने संकेत नहीं किया।
- (v) हि.चै.कामर्स ने सुझाव दिया है कि सीएचपीटी, यदि आवश्यक समझे तो, ग्रेनाइट प्रखंडों के लिए रु. 10,000/- प्रति पाली सैद्धान्तिक प्रभार लगा सकता है। इस प्राधिकरण को इस संबंध में पत्तन से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। जब कभी सीएचपीटी द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव दाखिल किया जाएगा, तब प्रदत्त सामान्य परामर्श प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए उसे कार्रवाई के लिए लिया जाएगा।

(vi) ग्रेनाइट प्रखंडों के निर्यात प्रेषण को हैवीलिफ्ट प्रभारों के लगाए जाने से छूट से संबंधित प्रावधान सीएचपीटी के प्रचलित दरमान में 50 टन क्रेन के साथ-साथ 150 टन फ्लोटिंग क्रेन के संबंध में प्रदत्त हैं। इसी प्रकार, जब निजी क्रेनों को पत्तन प्रचालनों के लिए अनुमति किया जाता है तब 50 टन क्रेन और 150 टन फ्लोटिंग क्रेन के संबंध में प्रदत्त क्रेनेज का 10% लगाना भी प्रदत्त है। इसलिए, यदि ग्रेनाइट प्रखंडों के प्रहस्तन के लिए निजी पक्षों द्वारा प्रहस्तन उपकरण अन्दर लाए जाते हैं तो ग्रेनाइट प्रखंडों के प्रहस्तन के लिए क्रेनेज के 10% छूट, दोनों मामलों - 50 टन क्रेन और 150 टन फ्लोटिंग क्रेन के मामलों में भी लागू किए जाने की आवश्यकता है।

(vii) यह महसूस करते हुए कि सीएचपीटी के दरमान में पिछले प्रभाव से संशोधन से जटिलताएं पैदा हो सकती हैं, संशोधनों को भावी प्रभाव से लागू करने के लिए हि.चै.कामर्स सहमत हो गया है। जैसाकि मार्च 2005 के प्रशुल्क मार्गदर्शियों की धारा 3.2.8 में अनुबंधित है, इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दरमान में संशोधन भारत का राजपत्र में अधिसूचना की तिथि के बाद 30 दिन बीतने पर लागू होगा।

8.1 परिणामस्वरूप और ऊपर दिए गए कारणों से तथा समग्र विचारविमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण सीएचपीटी के वर्तमान दरमान में निम्नानुसार संशोधन करता है:-

(i) अध्याय III (कार्गो संबंधी प्रभार) में मान -11 के अन्तर्गत वर्तमान नोट-6 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

“(6) निर्यात के लिए ग्रेनाइट पत्थरों को छोड़कर, पत्तन प्रचालन के लिए पक्ष के अनुरोध पर निजी क्रेनों को दरमान में विनिर्दिष्ट प्रभारों के 10% के भुगतान पर अनुमति किया जाएगा।”

(ii) अध्याय III (कार्गो संबंधी प्रभार) में मान-11 (II) के अन्तर्गत वर्तमान नोट-6 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

“(6) निर्यात के लिए ग्रेनाइट पत्थरों को छोड़कर, पत्तन प्रचालन के लिए पक्ष के अनुरोध पर निजी क्रेनों को दरमान में विनिर्दिष्ट प्रभारों के 10% के भुगतान पर अनुमति किया जाएगा। पक्षों को उनके अपने उपकरण लाने की अनुमति दी जाएगी, यदि वे उपकरण पत्तन न्यास के पास उपलब्ध नहीं हैं। यदि उपकरण पत्तन न्यास के पास उपलब्ध तो हैं किन्तु उनमें खराबी आ जाने के कारण, योजनानुसार अनुरक्षण के कारण अथवा किसी अन्य पक्ष को किराए पर दे देने के कारण उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं तो ऊपर विनिर्दिष्ट 10% प्रभार वसूल नहीं किया जाएगा।”

8.2 चेन्नै पत्तन न्यास के दरमान में उपरोक्त संशोधन, भारत का राजपत्र में इनकी अधिसूचना की तिथि से 30 दिन बीतने पर लागू किए जाएंगे।

रानी जाधव, अध्यक्षा

[विज्ञापन III/4/143/10-असा.]

**TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS
NOTIFICATION**

Mumbai, the 13th August, 2010

No. TAMP/37/2008-CHPT.—In exercise of the powers conferred under Sections 48 and 49 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the reference received from the Hinduстан Chamber of Commerce with regard to the collection of craneage charges by the Chennai Port Trust on granite blocks and amends the Scale of Rates of Chennai Port Trust as in the Order appended hereto.

325496/10-2

Tariff Authority for Major Ports

Case No. TAMP/37/2008-CHPT

Hindustan Chamber of Commerce

Applicant

ORDER

(Passed on this 23rd day of July, 2010)

The Hindustan Chamber of Commerce (HCC) vide its letter dated 11 December 2007 has made a representation with regard to the collection of cranage charges on granite blocks by Chennai Port Trust (CHPT).

2. The representation was forwarded to CHPT vide our letter dated 18 December 2007 for its comments. The CHPT was also requested to furnish a copy of the order reportedly issued by the Ministry of shipping in 1991, which was referred in the HCC letter.

3. The CHPT furnished its comments vide its letter dated 29 May 2008 along with a copy of the amendment to the Scale of Rates issued by the port vide notification dated 5 October 1994, exempting export granite blocks from Heavy Lift charges. Subsequently, the HCC vide its letter dated 31 May 2008 has furnished its comments on the points made by CHPT in its letter dated 29 May 2008. The representation of HCC, comments of CHPT vide its letter dated 29 May 2008 and comments of HCC thereon vide its letter dated 31 May 2008 are summarized and tabulated below:

Sr. No.	Points raised by HCC in its letter dated 11 December 2007	Comments of CHPT dated 29 May 2008 on the representation of HCC.	Comments of HCC dated 31 May 2008 on the comments of CHPT thereon.
1.	<p>Scale 11 – II Notes (4) of SoR of ChPT states that the heavy lift charges are not applicable for granite stones for exports. In 1991, Ministry of Shipping had issued orders exempting rough-granite blocks from heavy lift and cranage charges.</p> <p>The ChPT is interpreting the rules in its SOR in a manner which has made the export of granite blocks more expensive making the user pay a large sum of money by calculating the 10% as applicable for the 150 ton floating crane apart from hiring a private crane.</p>	<p>An amendment to the SoR was issued vide notification No.T2/23/3218/93/AR (Correction slip no.7) dated 5 October 1994 (Correction slip no.7) to the effect that the Export Granite blocks would not attract Heavy Lift charges. The notification stipulates inclusion of a conditions as given below:</p> <p>"No heavy lift cranage charges shall be levied on shipment of granite stones for Export, whenever Ship's own derricks are used."</p> <p>During the last general revision, in order to improve productivity and performance of the vessels, usage of private cranes was encouraged and accordingly, a provision was incorporated in Scale – 11 of the CHPT SOR, whereby the users bringing their own private cranes were required to pay 10% of the normal cranage charges applicable to the respective cargo/ capacity as per Port's SOR.</p> <p>Note (4) to Scale 11, Chapter-III of the Scale of Rates of ChPT states as follows:</p> <p>"Whenever packages</p>	<p>The Government vide its Notification no. T2/23/3218/93/AR (Correction slip no.7) dated 5 October 1994, have exempted heavy lift charge on rough granite blocks. Thus, calculation of 10% on the basis of rate of Heavy Lift charges is untenable and ab initio void.</p> <p>The Port has confirmed that the amendment made in the SoR with regard to allowing private cranes was to bring in efficiency and encourage use of private cranes. Thus note 6 to Scale 11 was incorporated, not to increase the revenue but to simplify the procedure.</p> <p>The Port has also confirmed that since the granite blocks are directly loaded from Trailer on to the ship, there is no collection of cranage charge. This justifies that the collection of 10% of the crane charge when no cranage is normally payable by this cargo is unfair. The collection of 10% charge makes the exports of granite blocks more expensive.</p> <p>Note (6) to Scale 11 of the SOR of CHPT may be amended as follows:</p>

	<p>HCC has requested to interpret the rules correctly and in its opinion 10% on crane hire charges as shown in Scale - 10 should be collected.</p>	<p>weighing above 30 tonnes are landed or shipped or directly delivered or directly loaded by Ship's own derricks at SQ 1 only without the use of the CHPT's 50 Tonne crane, charges shall be recovered at 50% of the rates as specified above excepting for export of granites stones."</p> <p>Note (6) to Scale 11 of the Scale of Rates of CHPT states as follows:</p> <p>"The private cranes shall be allowed on the request of the party for port operations on payment of 10% of the charges specified in the Scale of Rates."</p> <p>There is no provision in clause 6 for exempting granite blocks from payment of 10% charges for the deployment of private cranes. Since the granite blocks are directly loaded from Lorry/Trailer, there is no collection of craneage charge.</p> <p>It is only for the last two years Heavy Lift Harbour Mobile Cranes capable of handling granite blocks are available in the private deployment.</p> <p>If there was an intention to exempt the private cranes handling granite blocks from paying the 10% charges, the same would have been clearly mentioned in either Note (4) or Note (6) of the Scale - 11 of the CHPT SOR. In the absence of such a provision, it may not be correct on the part of the Port to accede to the request of the users and extend the exemption to private cranes handling granite blocks.</p> <p>TAMP may take an appropriate decision and communicate the same to the CHPT.</p>	<p>"The private cranes shall be allowed on the request of the party for port operations on payment of 10% of the charges specified in the Scale of Rates excepting for export of rough granite stones."</p>
--	--	---	---

4. In terms of clause 3.1.5 of the tariff guidelines 2005, this Authority can entertain representations filed by individual users if it involves fixation of tariff/ Scale of Rates. In view of the fact that the HCC has raised an issue regarding applicability of the conditionality prescribed in the SOR

3254 46710-3

and bearing in mind that CHPT desires this Authority to take a decision in this regard, it was decided to process the reference received from the HCC following the usual consultation process adopted.

5. Accordingly, a copy each of the reference received from the HCC vide its letter dated 11 December 2007, CHPT's response dated 29 May 2008 on the reference of HCC and HCC letter dated 31 May 2008 furnishing its comments on the points made by CHPT were forwarded to the concerned user organizations and additional users as suggested by the CHPT vide its letter dated 5 September 2008 for their comments. The comments received from the various users / user organisations were forwarded to CHPT for its comments. The CHPT furnished its comments on the feedback information.

6. A joint hearing in this case was held on 29 June 2010 in the premises of CHPT. The HCC and the CHPT made their submissions.

7. The proceedings relating to consultation in this case are available on records at the office of this Authority. An excerpt of the comments received will be sent separately to the relevant parties. These details will also be made available at our website <http://tariffauthority.gov.in>.

8. With reference to the totality of information collected during the process of the case, the following position emerges:

- (i). This Authority had passed an Order on 7 March 2006 revising the Scale of Rates of CHPT fixed in October 2002. The Scale of Rates approved in March 2006 contains provisions for levy of cranage for use of port's 50 tonne crane and 150 tonne floating crane. When a package of cargo weighing more than 30 tonnes is landed or shipped by ship's cranes only 50% of the prescribed charges are recoverable by the port from the users. However, export of granite blocks is exempted from the levy of 50% of the prescribed cranage charges.
- (ii). It is relevant here to mention that, based on the approval accorded by the Government of India, the CHPT had amended its Scale of Rates in October 1994 by a Notification dated 5 October 1994 to exempt export of granite stones from heavy lift charges whenever ship's cranes are used. This provision continued in the Scale of Rates of CHPT notified subsequently from time to time.
- (iii). The Scale of Rates approved by this Authority in October 2002 contained a provision authorizing the CHPT to allow private cranes for port operations on recovery of 10% of the charges specified in the then existing Scale of Rates of CHPT, if these equipment are not available with the Port Trust. The provision prescribed in the tariff Order of October 2002 was slightly modified, as proposed by the CHPT at the request of the users, in the tariff Order of March 2006 for levying the prescribed charge on private equipment even when such equipment are available with the CHPT. Incidentally, the tariff Order of March 2006 was passed based on the consensus proposal filed by the CHPT after their discussion with all concerned user organizations.
- (iv). Levy of 10% of the prescribed cranage charges for the cargo handled by private cranes is incidental to such cargo attracting the prescribed normal cranage charges. Since export consignment of granite blocks is exempted from the levy of normal heavy lift charges, absence of a corresponding provision exempting the granite blocks from levy of 10% charges when such granite blocks are handled by private cranes appears to be an omission in the Scale of Rates approved in March 2006. The Scale of Rates presented before this Authority at the relevant point of time was the outcome of CHPT's consultation with the user organizations. However, absence of relevant provision in the Scale of Rates for exempting granite blocks from levy of 10% charges was not pointed out by anybody.
- (v). The HCC has suggested that the CHPT can levy a notional charge of Rs. 10,000/- per shift for granite blocks, if it is necessary. This Authority has not received any proposal from the port in this regard. If and when such a proposal is filed by the CHPT, it will be taken up for processing following the usual consultation procedure prescribed.

(vi). Provision relating to exemption of export consignment of granite blocks from levy of heavy lift charges is prescribed in the existing Scale of Rates of CHPT in relation to 50 tonne crane as well as 150 tonne floating crane. Likewise, levy of 10% of the prescribed craneage when private cranes are allowed for port operations is also prescribed in relation to 50 tonne crane and 150 tonne floating crane. Therefore, exemption of 10% of craneage for handling of granite blocks, if the handling equipment is brought in by the private parties to handle granite blocks, needs to be made applicable both in cases of 50 tonne crane as well as 150 tonne floating crane.

(vii). Realizing that retrospective amendment to the Scale of Rates of CHPT may cause complications, the HCC has agreed for effecting the amendment prospectively. As stipulated in Clause 3.2.8. of the tariff guidelines of March 2005, the amendment to the Scale of Rates approved by this Authority will come into force after expiry of 30 days from the date of Notification in the Gazette of India.

8.1 In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority amends the existing Scale of Rates of CHPT as follows:

(i). The existing Note- 6 under Scale – 11(I) in Chapter III (Cargo related charges) is replaced with the following :

"(6). The Private cranes shall be allowed on the request of the party for port operations on payment of 10% of the charges specified in the Scale of Rates excepting granite stones for export."

(ii). The existing Note- 6 under Scale – 11(II) in Chapter III (Cargo related charges) is replaced with the following :

"(6). The private cranes shall be allowed at the request of the party for port operations on payment of 10% of the charges specified in the Scale of Rates excepting granite stones for export. The parties shall be allowed to bring their own equipment if those equipment are not available with the Port Trust. If the equipment are available with the Port Trust and not made available to the party due to its break down, planned maintenance or having been hired to other party, the 10% charge specified above shall not be collected."

8.2. The above amendments to the Scale of Rates of Chennai Port Trust will come into force after expiry of 30 days from the date of their notification in the Gazette of India.

RANI JADHAV, Chairperson

[ADVT. III/4/143/10-Exty.]